ness, we can have more time. We can spend our time on that. If these Bills are to be passed tomorrow, it would take three hours.

SHRI BUTA SINGH : It was agreed to by all Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You will have more time.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We do not have any business other than these Bills for tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You forget tomorrow. Tomorrow it will take more time.

SHRI BUTA SINGH : Shri Satyasadhan Chakraborty himself is pressing that Dowry Bill should be there, and that Land Acquisition Bill should also be there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am of the opinion that if you get more time for international situation, it is good.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : I am under the impression that for today the House will adjourn after the Call Attention is over.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If we get more time for international situation tomorrow, it would be better.

AN HON. MEMBER : Tomorrow we can sit beyond 6 O'Clock. We can sit late.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This Call Attention depends on Shri Atal Bihari Vajpayee. I think he will make a short speech. He will finish it. Then I will have to ascertain the sense of the House.

PROF. RUP CHAND PAL : How long are you going to sit today ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It depends on you. Now the Call Attention is over. You can sit for four hours, or for six hours or for one hour, as you complete the business. You are such capable people. I know.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : If someone decides you cannot sit at all ?

PROF. RUP CHAND PAL : How can you violate the recommendation of the Business Advisory Committee ? They have fixed up some time for the Bill. What is the time fixed for the Bill ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you go on technicalities, I can say that we can change the decision of the Business Advisory Committee also. The House is supreme. The House can always change decisions. All hon. Members should kindly cooperate with us. We are coming to the end of the Session. We will sit for more time.

We take up Calling Attention and afterwards we take up this Bill and two very small Bills as Shri Buta Singh suggested and we shall complete them. So that we will have more time tomorrow for the discussion on international affairs. I also think that this arrangement is good. Now, it is left to the House. If you want to complete in one hour, you can do it.

We now take up the Calling Attention. Mr. Suraj Bhan.

18.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported delay in replacing sales tax by additional excise duty on cement, paper, drugs, petrol and petroleum products as recommended by the Tripathi Committee

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कालिंग अटैन्शन इतना इम्पोर्टेन्ट है और वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी यहां नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : आएंगे।

श्री सूरज भान : आएंगे, ठीक है।

SHRI S.M. KRISHNA : By the time Mr. Vajpayee gets up, he will be here.

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें—

> "त्रिपाठी समिति की सिफारिश के अनुसार सीमेंट, कागज, औषधों, पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर विक्रय कर के बजाय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने में विलम्ब के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, there has been a long-standing demand by the trade, industry and general public for certain reforms pertaining to the sales tax levy in the country. As sales tax is mainly a State subject of taxation, any reforms in the sales tax system can be undertaken only in consultation with and with the co-operation of the States. Accordingly, a conference of Chief Ministers was held in September, 1980 to consider the matter, and as a follow-up, another conference of Chief Ministers was convened in February, 1981. In accordance with the resolution adopted in the conference held in February, 1981, an expert committee was appointed to study the financial implications of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for the levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products and the manner in which the financial interests of the States could be safeguarded. The committee headed by Shri Kamlapati Tripathi, M.P. submitted its report on 29th January, 1983. The report was subsequently placed on the Tables of both the Houses of Parliament on 29th April, 1983. The Committee, in its report, had evolved a formula for the distribution of additional excise duty on the five commodities in question amongst the States so that they did not suffer any financial losses and their resources mobilisation was not hampered. In accordance with the resolution of the conference of Chief Ministers held in February, 1981, the report of the expert committee was considered by a conference of Chief Ministers held on 2nd November, 1983. In the conference held in November, 1983, a large number of Chief Ministers indicated their acceptance, in principle, of the scheme suggested by the Tripathi Committee for introduction of additional excise duty in lieu of sales tax. Some of the Chief Ministers, however, indicated that they were not in a position to accept the scheme recommended by the Tripathi Committee. While thanking the Union Finance Minister for implementing the resolution adopted by them in February, 1981, the Chief Ministers resolved that efforts should be continued to bring about consensus amongst State Governments on these issues. The resolution adopted at the Chief Ministers' conference held in November, 1983 has been noted for suitable action and efforts to bring about a consensus among the State Governments in the matter are continuing.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, इस सिलसिले में 18 नवम्बर, 1983 को वित्त मंत्री से एक जवाब किया गया था। जो स्टेटमैंट उन्होंने उस वक्त दिया था, वही स्टेटमैंट आज दिया गया है। इसमें एक छोटा सा सेनटेंस ऐड किया हुआ है :—

> "The resolution adopted at the Chief Ministers' conference held in November, 1983 has been noted for suitable action."

नवम्बर, 1983 से लेकर अब तक सरकार ने सिर्फ रेजोल्यूशन को नोट कर लिया है। वह क्या सूटेबल एक्शन लेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

जनता, इन्डस्ट्री और व्यापार की पुरानी मांग है कि सेल्ज टैक्स के ढांचे में बुनियादी तबदीली की जाए। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में यह बात कही गई और कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में भी यह बात कही गई। मैं कांग्रेस के चुनाव

घोषणापत्र में से एक छोटा सा सेनटेंस पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

> "The Congress (I) will review the existing tax system and restructure it so as to reduce the burden on the middle class, to remove the harassment of the small trader and to bring about equitable responsibilities on all affluent sections for the benefit of the society as a whole."

इस सम्बन्ध में 1980 में चीफ मिनिस्टर्ज की कांफरेंस हुई। उसके बाद स्वर्गीय सुखाड़िया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उनके देहांत के बाद 1 मार्च, 1982 को त्रिपाठी जी को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 29 जनवरी, 1983 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार ने 29 अप्रैल, 1983 को उस रिपोर्ट को सदन-पटल पर रख दिया।

उसके बाद 2 नवम्बर, 1983 को चीफ मिनिस्टर्ज की कांफरेंस बुलाई गई। उसमें अक्सर मुख्य मंत्रियों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी संशोधनो के साथ इसको लागू कर दिया जाए। उनके संशोधनों में कुछ ये हैं : (1) उन स्थलों को कम करना, जहां एक ही वस्तु पर कर लगता है, (2) मूल्यों में और देश के भिन्न-भिन्न मार्गों में जिन्सों के टैक्सों की दरों में एकरूपता लाना, (3) व्यापारियों को परेशान करने की गुंजाइश को कम करना।

लेकिन कुछ मुख्य मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि एक तो इससें राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे और दूसरे, राज्यों की आमदनी और आमदनी के जरिये कम हो जाएंगे। तीसरी दलील यह दी गई कि सरकारिया कमीशन बैठा है, इसलिए फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाए। मैं समझता हूं कि सरकारिया कमीशन की बात तो बेमानी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनकी दो बातों—आमदनी कम होने और अधिकार कम होने—में वजन जरूर है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा।

इस बिक्री कर की शुरुआत 1937 में हुई थी। जब राजाजी ने मद्रास में प्राहिबिशन लागू की—शराब पर पाबन्दी लगा दी, तो उसके बाद सरकार को जो घाटा हुआ, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक गैलन पैट्रोल पर एक पैसा सेल्ज टैक्स लगाया। लेकिन 1937 के बाद यह बिक्री कर शैतान की आंत की तरह बहुत फैल गया है। कहां उस वक्त एक पैसा और कहां आज 14, 15 परसेंट लगा हुआ है। फर्ज कीजिए कि एक स्टेट में 10 फीसदी और पड़ौसी स्टेट में 15 फीसदी सेल्ज टैक्स लगा हैं, तो स्मगलिंग के लिए रास्ता खुल जाता है।

कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सेल्ज टैक्स का नम्बर ले लिया और दुकान खोल दी, दो साल तक काम किया, कोई बिक्री कर त दिया और दुकान बढ़ा दी, फिर एक नए नाम सें दुकान खोल दी, एक नया बिक्री कर का नम्बर ले लिया, बस, पिछला हिसाब-किताब खत्म हो गया। इस तरह से सेल्ज टैक्स की चोरी होती है। आम राय है कि बिक्री कर में 70 फीसदी चोरी होती है।

इसके साथ-साथ त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट में पांच चीजों पर सेल्स टैक्स हटाने की सिफारिश की गई है। मैं समझता हूं—पांचों चीजों के बजाए सभी चीजों पर से बिक्री कर हटाया जाना चाहिए। इन पांच चीजों पर तो फौरी तौर पर हटा दिया जाना चाहिए। मैंने त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट देखी है, उसमें एक साल के आंकड़े दिए हैं—1981-82 सें इन पांच चीजों पर 1 करोड़ 40 लाख रुपया सेल्स टैक्स के रूप में वसूल हुआ और सभी चीजों को मिलाकर सारे देश सें 4200 करोड़ वसूल हुआ। लेकिन यह 4200 करोड़ चोरी के बाद दिखाया गया है, एक्चुअली इसको 12,600 करोड़ होना चाहिए था। इसका साफ मतलब यह है कि 8,400 करोड़ की चोरी एक साल सें सेल्स टैक्स के रूप में की गई। इसका मतलब यह भी है इतना काला धन बढ़ा और एक पैरेलल इकोनोमी पैदा हुई।

[श्री सूरज भान]

इसके साथ और भी कई तरह की चीजें जुड़ती हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रक देहली से राजस्थान जा रहा है, बीच में हरियाणा है तो वहां पर बीच में उस ट्रक को सेल्स टैक्स के अधिकारी रोक लेंगे। ऐसी भी मिसालें हैं दो-दो, तीन-तीन दिन तक ट्रक रुके रहे। जब तक मुट्ठी गरम नहीं होती रिश्वत के देवी-देवताओं की, तब तक ट्रक आगे नहीं जा सकता। मेरी तो यह भी जानकारी है कि सेल्स टैक्स बैरियर्स पर एप्वाइंटमेंट के लिए छोटे-छोटे मुलाजिम भी एक लाख रुपए की रिश्वत देते हैं। लाख देकर बाद में वे करोड़ों कमाते हैं। तो इस तरह से जनता को परेशानी होती है और सरकार को भी नुकसान पहुंचता है। मैं तो समझता हूं कि अगर इस बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाए तो देश में काला धन कम होकर एक चौथाई रह जाएगा। अभी बहुत बड़ी मात्रा में काला धन सेल्स टैक्स की चोरी के कारण पैदा हो रहा है। जो छोटे दूकानदार है उनको, यह जो इंसपेक्टर राज हैं, वह बहुत तंग करता है। कोई भी ईमानदार दुकानदार अपने बेईमान पड़ौसी दुकानदार के मुकाबले में अपना धंधा चला ही नहीं सकता है, उसकी दूकान बन्द होने की नौबत आ जाएगी। इन हालात में मैं और मेरी पार्टी इस बात के पक्ष में हैं कि बिक्री कर केवल इन पांच चीजों पर ही नहीं, सभी चीजों पर से हटा दिया जाना चाहिए और उसकी जगह पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाना चाहिए ताकि सारे देश में चीजों की कीमतों में एकरूपता आ सके। अभी तो किसी चीज पर एक राज्य में 15 परसेन्ट सेल्स टैक्स है तो दूसरी स्टेट में 7 परसेन्ट है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को इस बात का यकीन दिलाए कि उनको आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर कमी होती है तो उसको स्पेशल ग्रांट देकर पूरा किया जाए। मैं तो इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं कि यदि आवश्यकता समझें तो विधान में तरमीम करके एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार सेन्टर के बजाए स्टेट्स को दे दिया जाए ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न होने पाए और यह अश्योर हो जाए कि उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी।

इसमें एक प्रकार की गड़बड़ और भी चल रही है। अभी ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स पर 5 परसेन्ट सेल्स टैक्स है। मान लीजिए स्पेयर पार्ट है बाल वियरिंग—ट्रैक्टर में बाल वियरिंग बदला जाएगा तो 5 परसेन्ट का सेल्स टैक्स लगेगा, अगर वही बाल वियरिंग मशीन में बदला जाएगा तो सेल्स टैक्स 7 परसेन्ट हो जाएगा, मोटर कार में बाल वियरिंग बदला जाएगा तो सेल्स टैक्स 10 परसेन्ट हो जाएगा और अगर हवाई जहाज में बदला जाए तो मुझे मालूम नहीं कितने परसेन्ट सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता होगा। इससे एक अन्दाजा लगता है कि गड़बड़ कितनी हो रही है।

मेरे पास एक रिपोर्ट है "रिवीजन आफ टैक्स", इसमें काफी लम्बी-चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर संक्षेप में ही बता देता हूं।

बोरोलीन की ट्यूब, जो कि दवाई नहीं है, के बारे में पी० ए० सी० की रिपोर्ट के पेज-3 पर जो लिखा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

In this report the Committee have dealt with the case of classification of a product BOROLINE manufactured by M/s G.D. Pharmaceuticals which contains 1% of boric acid. This product has been classified as a patent and proprietary medicine which falls under Tariff Item 14E and attracts duty at the rate of 12 1/2 per cent *Ad Valorem*.

अगर इसको आइटम-14 एफ (1) में लेते तो दवाई सहीं रहती और 100 परसेंट चार्ज होता। ···(व्यवधान))···मैं बता रहा था कि टैक्स इवेजन कैसे होता है। इसी तरह सेल्स टैक्स में भी होता है। मैं एक्साइज के बारे में एक और बात कहता हूं। एक आइटस है आईब्रो-पैंसिल, दूसरी बिन्दी पैंसिल है। वह आईटम-68 में है। इसलिए एक्साइज इव पर आठ परसेंट है यदि यह आइटम 14-एफ (1) में होता तो 100 परसेंट होता। इसी प्रकार आजकल लिपिस्टिक ऐसी इजाद की है

जो ब्रुश से लगाई जाती है। उससे कहा गया कि लिपिस्टिक में एग्जैम्पशन कैसे मिलेगा? बनाने वाले ने कहा कि इसमें स्टीक तो हैं नहीं; इसलिए एग्जैम्पटेड हैं। लोन इस तरीके से बचकर निकल जाते हैं। इस कमेंटी के चेयरमैन त्रिपाठी जी हैं, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अब रूलिंग पार्टी के वर्किंग प्रैजीडेंट हैं। नॉन वर्किंग प्रेजीडेंट नहीं हैं। उनकी सिफारिश को तो सरकार को मान लेना चाहिए। रूलिंग पार्टी के सहामंत्री श्री राजीव गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि हम सिर्फ पांच आइटम्स पर ही नहीं सभी चीजों पर सेल्स टैक्स हटा देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): भीकू रास जी के कहने से कह देते हैं।

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक): मेरे कहने सें नहीं कहते हैं। उनको विश्वास होगा।

श्री सूरज भान: उनके विश्वास से विश्वासघात तो न करे सरकार।

श्री भीकू राम जैन: आपका ससर्थन पहले मिलता तो हो जाता। देर में समझ आई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सबसे पहले तो हमें समझ आई थी। आपको देर से आई।

श्री भीकू राम जैन: आपने तो वायदा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ।

श्री सूरज भान: बिक्री कर वसूल करने के लिए चार्जेज दो तीन परसेंट आते हैं, यदि इसको एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में शामिल कर लें, स्टाफ वही रहेगा और खर्च 1% से भी कम होगा इसमें सरकार को भी फायदा होगा। आदरणीय प्रणव मुखर्जी आ गए हैं, आखिर में मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाकी सवाल तो श्री एस० एम० कृष्णा जी भी बता देंगे। सवाल यह है कि आप 28 मई को मुख्यमंत्रियों की कांफ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। पिछले एशारेंसेस, चुनाव घोषणा पत्र का वायदा, वर्किंग मैंजीडेंट की सिफारिश और महामंत्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए क्या 28 मई को आप फैसला करने जा रहे हैं कि इन पांच चीजों पर ही नहीं; सारी चीजों पर बिक्री कर हटाकर छोटे दुकानदारों को राहत देंगे और भ्रष्टाचार को कम करेंगे?

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I just wanted to clarify one point. I agree with the hon. Member that these are the rationable for abolition of the sales-tax. But the moot point is that I have to convince the State Chief Ministers and they have to agree with this logic. If not, the only option left to me is to take a vote in the conference of Chief Ministers which I wanted to avoid. As I said, on an earlier occasion when I had convened the State Chief Ministers' Conference on 2nd November and the whole idea was being discussed opinions differed. It is not the practice to state who said what, who supported or who opposed it. But I said that after the conference was over I will try to have discussion with them so that we can work out a consensus.

When the Janata Party was in the office, they also tried. We are also trying. But this is a matter which the hon. Members are fully aware of. It is not exclusively within our domain. Otherwise I can declare all these items and bring them under Central Act and levy a uniform 4%. So, keeping that in view we are trying to impress upon them and the Committee's reports are before them. We have had some discussions. Though the subject was limited to consignment tax, again I have convened a meeting. We are trying to work out a formula. It is not that because somebody is wanting something and we are not trying to do that. In this area, there are no two opinions.

SHRI SURAJ BHAN: Consensus does not mean unanimity.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Obviously, consensus is not there, therefore, we have to try to work it out in the Conference.

SHRI SURAJ BHAN : You amend the Constitution as I have suggested.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : If Mr. Vajpayee supports us in the Chief Ministers' Conference, it will help us and he can do it.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : What about Kerala ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : You extend your support first.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, बिक्री कर से उपभोक्ताओं को, जनता को और सरकार को, दोनों को हानि होती है और लाभ भ्रष्टाचारी अधिकारियों, नम्बर दो का धन्धा करने वाले व्यापारियों को होता है, इस लिए इसको समाप्त करने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। आपने अभी इसके बारे में जवाब भी दिया है, जनता सरकार ने भी इसको खत्म करने के लिए अपने मैनीफेस्टो में रखा था, वह सरकार सवा दो साल तक ही चल पाई, उसने भी इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद 1980 में जब आप सत्ता में आए तो उस समय आपने भी अपने मेनीफेस्टो में इसको रखा था, चार वर्ष से अधिक का समय गुजरने जा रहा है, दो-तीन बार आपने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया और सम्मेलन में डिफरेंसेज सामने आए, इससे राज्यों की जो आर्थिक क्षति होती है, जब तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई कारगर फार्मूला नहीं होगा, जब तक सभी राज्यों को यह विश्वास नहीं हो जाएगा कि बिक्री कर के द्वारा वे अपने विकास कार्यों के लिए जो धन जुटाते हैं, किसी दूसरे तरीके से उसकी पूर्ति नहीं होती है, तब तक वे उसका विरोध करते रहेंगे।

इस सम्बन्ध में मैंने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, उनके अनुसार सब राज्यों का मिलाकर कुल 5403.9 करोड़ रुपया सेल्ज टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। यदि अलग-अलग राज्यों का देखा जाय तो—

महाराष्ट्र	1065 करोड़ रुपये
तमिलनाडू	623.7 करोड़ रुपये
गुजरात	481.2 ,, ,,
वेस्ट बंगाल	427.7 ,, ,,
यू० पी०	416.4 ,, ,,
आन्ध्र प्रदेश	410.8 ,, ,,
कर्नाटक	330 ,, ,,
केरल	288.4 ,, ,,
बिहार	259.5 ,, ,,
मध्य प्रदेश	358.5 ,, ,,
पंजाब	246.8 ,, ,,
राजस्थान	209 ,, ,,
हरियाणा	161 ,, ,,
उड़ीसा	109.3 ,, ,,
आसाम	66.2 ,, ,,
जम्मू-काश्मीर	21.1 ,, ,,
अन्य राज्य	10.7 ,, ,,

यह आमदनी उन राज्यों को बिक्री कर के द्वारा होती है जिससे उन राज्यों के विकास की योजनाएं चलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी जो यह धारणा है कि इसके द्वारा उनकी योजनाएं चलती हैं, वास्तविकता यह है कि इससे कई गुना राशि भ्रष्टाचार में चली जाती है। उससे करोड़ों जनता पीड़ित होती है ; इसलिए यह बिक्री कर हर हालत से समाप्त होना चाहिए। त्रिपाठी कमेटी ने जो फार्मूला इसके लिए बताया है, उसके अनुसार काम किया जाना चाहिए। अभी तक इस ओर क्या कार्यवाही की गई है और राज्यों की

क्षति पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बिक्री कर की दर हर राज्य में अलग-अलग है। इससे कीमतों में एकरूपता नहीं आ पाती। टायर की कीमत एक राज्य में कुछ है और दूसरे राज्य में कुछ और है। इससे बड़ा घोटाला होता है और लोग लाभ कमाते हैं। इसलिए बिक्रीकर लाभदायक नहीं कहा जा सकता।

चार वर्ष का समय बीत चुका है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस ओर क्या करने जा रही है। आपने आम जनता को वादा किया था, क्या अब जनता को धोखा देने जा रहे हैं। या फिर जैसे पंजाब समस्या और आसाम समस्या चली आ रही है उसी तरह से यह समस्या भी चलती रहेगी और मीटिंग्स भी चलती रहेगी। इस तरह से काम नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं और क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आम जनता को लाभ हो सके।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, regarding the losses of the States, hon. members are aware of the formulation made by Tripathi Committee. There it has been taken care that the normal growth rate which the States are expecting on these 5 particular items will be maintained if it is realised as additional excise duty. There is no question of abolition of sales tax. There is only the question of rationalisation so that sales tax can be gradually replaced by additional excise duties. There are difficulties, no doubt, and because of those difficulties only the question of rationalisation is coming up. At the same time, the hon. members are also aware of the fact that the States have mopped up their resources by utilising this instrument. If we just look at it from the States' angle and from our practical experience, it can be seen that irrespective of their Party position, the States have considered it one of the most important instruments through which they can mobilise resources and meet their requirements. So, what we are trying to impress upon them is that if they accept the recommendations of the Tripathi Committee, we would ensure that on these five items there will not only be no net loss of revenue on this account, but they can also have a reasonable growth even in the additional excise duty.

And Sir, it is not just an empty promise. As the hon. members have noted, even during this year's budget, in order to reach the targeted figure of 8.5 per cent which was recommended by the Study Group, I have transferred a part of the basic excise duty, i.e. about Rs. 70 crores, when I found that I could not increase additional excise duty on other items. When I was presenting the Budget I had said that I am increasing the duties on tobacco and cigarettes, and the Members immediately started laughing. But it was just a transfer from basic excise duty to additional excise duty. I am referring to this particular point in order to impress upon the hon. member that we wanted to ensure that the States' interests would be protected.

But it is not the point of either the hon. Members sitting here, or of myself that we have done enough to protect their interests. They themselves should feel convinced. We are trying to do so. Therefore, unless we are in a position to evolve—I am repeating it—some sort of a consensus and build up that mutual rapport between the States and the Centre on this issue, it will be difficult for us to take a decision unilaterally, and we did not want to take a decision unilaterally. That is why we waited.

A number of conferences have taken place. My colleague, Mr. Venkataraman convened two conferences of Chief Ministers. I myself have convened two, and one more is being called. I do hope it will be possible for us to work out some mechanism through which it would be possible to meet the demand.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, 15 फरवरी 1981 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि वनस्पति, ड्रग्स एण्ड मैडीसीन्स, सीमेंट, पेपर एण्ड पेपर बोर्ड्स और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगे हुए बिक्रीकर को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में बदलने के सवाल पर विचार करने के लिए एक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

एक्सपर्ट कमेटी बनायी जाए। उसी बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-काश्मीर ने सिद्धान्ततः अपना विरोध प्रकट किया था। जो प्रस्ताव पास किया, उसकी एक प्रति मेरे पास है। उसमें लिखा हुआ है कि :

> "After a brief discussion, the resolution was adopted by the Conference. The States of West Bengal, Kerala and Jammu and Kashmir, however, did not, on principle, agree with the resolution."

इसमें कर्नाटक और गुजरात का भी नाम नहीं है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : In 1981, you were not there ; you friends were not there.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर, केरल है। इसके बाद और बैठकें हुई। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी ईमानदारी से अपने मेनिफेस्टो पर अमल करने की कोशिश की है। मगर, कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों और जो गैर-कांग्रेसी राज्य-सरकारें हैं, उनको यह चिंता है कि बिक्री-कर के अलावा आमदनी का और कोई स्रोत उनके पास नहीं है। विकास की आवश्यकताएं और लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं। राज्य सरकारें कहां से साधन जुटाएं? इसलिए, बिक्री-कर को एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी में बदलने का सवाल, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का सवाल बन गया है और राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का सवाल भी बन गया है। मेरी, मुख्य मंत्रियों से, श्री हेगड़े से और मार्क्सवादी मित्रों से भी चर्चा हुई है। उनकी शिकायत यह है कि जब केन्द्र सरकार एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो उसकी दर कम रखती है। एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी से जो आमदनी होती है, वह पर्याप्त नहीं होती। आप कोई भी फार्मूला निकाल लें। आपने राज्यों को संतुष्ट करने के लिए फार्मूलों की चर्चा की है। त्रिपाठी कमेटी ने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया है। लेकिन, राज्यों की कठिनाई उससे दूर नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार, वह राज्यों को देने को तैयार है? यह ठीक है कि इसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा और पावर्स के डेलीगेशन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन देश का, उद्योग का, व्यापार का और उपभोक्ता का हित इसमें है कि जहां कारखाने में माल बनता है, फैक्टरी से माल निकालते समय टैक्स ले लिया जाए। वह चाहे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ले। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन, अगर आमदनी बढ़ानी है, परेशानी रोकनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी घटाना है और भ्रष्टाचारी तथा रिश्वतखोरी पर भी प्रहार करना है तो आपको एक बुनियादी फैसला करना पड़ेगा कि जहां माल बनता है उन फैक्ट्रीज के दरवाजे पर ही टैक्स लेंगे। केन्द्र और राज्यों के झगड़े में इस मूल बात को हम अपने ध्यान से ओझल न होने दें। क्योंकि व्यापारी तो उपभोक्ता से सेल्स टैक्स लेता है, इसलिए वह टैक्स वसूल करने की एजेंसी मात्र है। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह व्यापारी आपसे पूछता है कि आपको कैशमीमो चाहिए? इस तरह जो टैक्स वे लोग बचाते हैं, वह तो सरकारी खजाने में आना चाहिए—भले ही केन्द्रीय खजाने में आये या राज्यों के खजाने में जाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सवाल पर थोड़ा गहराई से जाकर क्या आप एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार प्रदेश सरकारों को देने के लिए तैयार हैं या नहीं?

Are you prepared to empower the State Governments to levy additional excise duty? You change the nomenclature. I don't mind. But the central purpose should be to levy tax when goods come out from the factory.

इसके बिना आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपने टोबैको, क्लाथ एण्ड शुगर पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, आपका इस सम्बन्ध में अनुभव या एक्सपीरियेंस क्या है। क्या वह तजुर्बा अच्छा नहीं

है अथवा इसके बारे में आपके पास राज्य सरकारों से शिकायतें आ रही हैं। यदि इन तीन वस्तुओं पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का एक्सपैरिमैंट सफल रहा है तो पांच अन्य वस्तुओं पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का आप विरोध क्यों करना चाहते हैं। दूसरी बात स्टेटमैंट में मेरी समझ में यह नहीं आई, जहां आप कहते हैं—

In your statement, you say as follows :

> "In the Conference held in November, 1983, a large number of Chief Ministers indicated their acceptance, in principle, of the scheme suggested by the Tripathi Committee for introduction of additional excise duty in lieu of sales tax. Some of the Chief Ministers, however, indicated that they were not in a position to accept the scheme recommended by the Tripathi Committee. While thanking the Union Finance Minister for implementing the resolution adopted by them in February, 1981, the Chief Ministers resolved that efforts should be continued..."

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Will you read the next one ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It says as follows :

> "Efforts should be continued to bring about consensus amongst State Governments on these issues."

Why did they thank the Finance Minister? For what purpose? They did not accept your recommendation.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : You ask them ! (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The Finance Minister is known for his persuasive power. I do not know how he has failed to convince the other Chief Ministers. But we should not import party politics into this ; there should be no idea to deprive the States of their financial power to raise resources. But solution can be found. If the demands of the States are considered with sympathy and a formula is evolved, it is good ; so that taxation structure can be changed without reducing the income of the States.

May I have an assurance from the Finance Minister before this Lok Sabha is dissolved :

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Why do you want to dissolve it ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is bound to be dissolved. Is there any proposal to extend the term of the Lok Sabha ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It will have its natural expiry. Why should it be dissolved ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I stand corrected. Before the next general elections, you have made a commitment to the people and people expectations have been roused. There was a *bandh* by a mercantile community dealing in papers and card boards. The other day, the druggists had gone on strike all over the country. So, you have raised the expectations and your performance must match with it. So, I would like to have an assurance from the Finance Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The leader of that strike is also sitting here.

AN HON. MEMBER : His name is not on the list. He has not agreed to it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : His action is appreciated.

मान्यवर, इनके लिए चांदनी चौक में निकलना मुश्किल हो रहा है। हमें तो लोगों ने ढाई साल में हटा दिया था।

SHRI BIKHU RAM JAIN : Then I will never allow them to take out a strike.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : People had given four years. And we were rejected only after two and a half years. But now the patience is giving way. So, do not tax the patience any more. The Finance Minister should use all his persuasive powers and evolve a formula that will convince the States which will achieve the desired results,

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Three issues have been raised by Shri Atal Bihari Vajpayee. First, I would not like to—I would agree with him in this—inject any party element or partisan elements in it. But the fact remains that in February 1981 although three Chief Ministers did not agree even with the resolution we appointed a Committee to look into the question of replacing sales tax by additional excise duty. It was an expert committee of those three Chief Ministers.

Unfortunately, all the representatives of the State Governments belonged to the Opposition, including Kerala ! Kerala was represented by Mr. Nayanar. It was in February 1981. I think now Mr. Vajpayee will realise this.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Kerala will fall in the same line.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Kerala, Jammu and Kashmir and West Bengal, these three States, you mentioned. West Bengal was represented by its Finance Minister, Dr. Ashok Maitro ; Jammu and Kashmir by Mr. D.D. Thakur, Finance Minister, and Kerala by its Chief Minister, Mr. Nayanar. But I am not going into that aspect. The major important point which he has made is that these States did not agree. I am not telling them that they should accept my word as assurance. You go to the facts. What is the fact ? Now in 1956-57 these three items were brought within the purview of additional excise duty, that is, tobacco, sugar and textiles. If you look at the growth of sales tax, additional excise duty, and basic excise duty, and calculate the overall percentage what has been the growth—and I have the figures before me—in 1958-59 sales tax was Rs. 123.9 crores, in 1983-84 it has increased to Rs. 5,564 crores; Central excise which was Rs. 312.94 crores in 1958-59 has gone up to Rs. 10125.33 crores; and additional excise duty which is collected by the Centre and given to the States was just Rs. 16.12 crores then and it has gone up to Rs. 672.81 crores. But in absolute figures it does not lead us to any conclusion. Therefore, we have to take the growth in terms of percentage. The growth in terms of percentage as far as the sales tax is concerned, from 1958-59 to 1983-84, the average of annual growth rate is 16.73 per cent. And what is the growth of the additional excise duty, which is collected by the Centre and distributed to the States ? The average of annual growth rate is 17.07 per cent during this period. And when I place these facts I do not know what else I can do to convince them. Even if you look at the Kamlapati Tripathi Report in respect of those five items, the first category which consists of paper, paperboards, drugs and medicines, and in the second category come the petroleum products and cement, and you yourselves will be convinced that the formula which has been formulated and declared is meant to safeguard the interests of the States.

Therefore, it is neither the question of arithmetic nor of fact. I am sorry to point out that it is the question of attitude and approach.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : They do not trust the Central Government. That is the difficulty.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It is not so.

The second proposition which you have made—I do not know how you have brought that idea—is that the power to levy additional excise duty should be given to the States. If we give this power to the States, I am afraid the Bengal Government will have one rate of taxation on a tyre factory in Bengal and UP Government will have another rate of taxation on a tyre factory in UP. Then exactly you will have the same system of sales tax, which is not going to help us. Unless you have the uniform rate of taxation, the basic objective which you have in mind, will not be served.

The first speaker was saying that the administrative cost of collecting the sales tax is two to three per cent and on additional excise duty it is 0.6 to 0.8 per cent. How are we getting this ? Because we are collecting the rax at a single point. We are utilising the same machinery to collect the additional excise duty. But the moment we give this power to the States, under what system we will say that all the States will have uni-

form tax system ? That proposition cannot be accepted and it will not lead to the desired result which you want to have. Moreover, the benefit will go to the States where manufacturing units are located. There is a difference between the consuming states and the producing States. Consuming States are suggesting to me that we should have a common pool system from where it will be distributed. The manufacturing States are suggesting that since it is being manufactured in our States, we should have the advantage. Even looking at the two completely different propositions, in the Conference which I had, a suggestion was made that we can make some sort of compromise by having partly pooling system and partly as incentive to the manufacturing States. We are working out some modalities. I hope, it would be possible for us to come to some conclusion at the next meeting. Therefore, we are trying to prevail upon them. The Resolution which the hon. Member has quoted, every word of it I got the approval of the Chief Ministers and their representatives present there. They agreed with me. Otherwise, there would have been a situation that some of the Chief Ministers would have said that they do not want it and some of them would have said that they want it. Naturally if the opinions are clearly divided, then we have to take a decision on the basis of either majority or minority. But that we have avoided. Hon. Members will also agree with me that it is not desirable particularly in such matters. So, I am trying to work out a consensus which will help us.

In regard to the persuasive power, if my persuasive power is not adequate I would like to get it supplemented by the persuasive power of my good old friend, Mr. Vajpayee. If I can request him, through you, Sir, that let him exercise..... (*Interruptions*).

SHRI SATISH AGARWAL : Only with regard to one State.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : That would be adequate for me now. I do hope here itself not only there is consensus but if I may be permitted to say so, perhaps there is unanimity between me and Mr. Vajpayee or all the Members who are present here. I cannot speak on behalf of CPI(M) Members because immediately he may jump and say, no, he does not agree, but apart from that a large section of the Members of this Parliament, a large section of the public opinion—trade, commerce and industry, various Chambers of Commerce, economists—also pointed out that primarily they are concerned with the net size of the kitty. And this is the point I am trying to emphasise.

Whether you have the power to impose the duty or not is important but what is much more important is whether your net kitty will be smaller or bigger. We can discuss in detail about the formulation of the mechanism. If you find, you can come out with a better formula, I have no objection to accept that and make a test of it but on principle we shall have to agree that sales tax ought to be replaced by additional excise duty in respect of these items and then the formula to the entire satisfaction of the States concerned could be worked out. And I have no difficulty in doing so. So, we are trying to prevail upon them and trying to work out something.

I had told at one point of time when we were having discussions that, look, we cannot go on indefinitely on this issue, there should be some time fixed. I do agree with Mr. Vajpayee that there is an expectation, particularly in the trade and industry circle, that something should be worked out and if it cannot be done, within the system, we shall have to tell them that yes, we tried but we could not do it or we shall have to take a decision in the process of decision-making, majority-minority view. Obviously, we cannot have a situation where every time minority view will prevail upon the majority, particularly in this area. Today I am sitting here, if tomorrow Mr. Satish Agarwal takes this seat, why would he like to take the trouble ? When I present the Budget or any Finance Minister presents the Budget, he will have to do it, it is his duty. And for whom are you increasing the duty ? It is not coming to your Central coffer. You are increasing for others but you are getting all the gullies. You will recollect that in the first year, 1982, when I increased the Additional Excise Duty substantially, then the principal opposition came from Mr. Somnath Chatterjee, he is not here. When I explained to him that whatever has been

[Shri Pranab Mukherjee]

done, you will be a net beneficiary out of it, be rectified it. So, it is not very pleasant job for any Finance Minister to impose duty but we are taking that responsibility not with the intention to deprive the States of their legitimate share but to ensure the normal growth that they are having. In this connection, I would like to point out one thing that a very wrong analogy is being attempted. When I was talking of the sales tax that it increased from Rs. 123.9 crores to Rs. 6,310 crores, it is not that there has been a vertical expansion, there has been equally a horizontal expansion. That means, the number of commodities which were under sales-tax in the earlier years, has increased. But in the Central Excise areas you will appreciate that except item 68 which was introduced in 1975, and that too as a process of collecting census, from 1958-59 to 1975-76 if you analyse the growth of the Central Excise, you will find that the growth has been vertical, not horizontal, but the expansion of the revenue in sales-tax has been both vertical and horizontal.

Therefore, when somebody makes an attempt to compare that the Sales-tax growth has been much more than the excise duty, they will find that the excise duty growth has been vertical. I am not talking of additional excise duty. The additional excise duty growth has been a little more. The average of salestax growth rate was 16.73 per cent from 1958-59 to 1983-84. The average additional excise duty growth rate is 17.07 per cent from 1958-59 to 1983-84. But even in the basic excise duty the growth has been vertical. That means the subsequent Finance Ministers increase the rate of duties. I do not say that there has been no horizontal expansion. Some horizontal expansion has taken place, but it is much less compared to that of the sales-tax.

To conclude, Sir, my point is that there are no two opinions on the need to replace the sales-tax by additional excise duty. Everybody appreciates that the States' interests should be protected and there should be no loss so far as the States are concerned. On the other hand there should be some mechanism through which we can ensure a reasonable growth in their revenue, if these items are taken out of the purview of the sales-tax and brought within the purview of the additional excise duty.

The third thing which we are trying to do is that we are working out a consensus. I hope with the goodwill, support and cooperation of the Members it would be possible for me. I am contemplating of circulating the proceedings of this discussion to the Chief Ministers beforehand so that they know the views at least of Shri Vajpayee and others so that they can also make up their mind to that extent.

19.02 hrs.

BANKING SERVICE COMMISSION BILL—*Contd*

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : Sir, face is not always the index of the mind. On the face of it this Bill looks as innocuous as our Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : I am not innocuous.

PROF. RUP CHAND PAL : You look like that. Of course, you are highly sophisticated, but you look innocuous.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : And I am most mischievious according to them ?

PROF. RUP CHAND PAL : I will come to that also.

Sir, I was rather bewildered what was the hurry in bringing in such a piece of legislation at the fag end of the day and also at the fag-end of the Session ? There seems to be some reason behind it. I was trying to ponder over this that the Government had come to power in 1980 and the recommendation of the Banking Service Commission was there. There might be some problem in 1978, but since 1980 the Government did not find enough time to apply its mind to it. And now in a hurry it is coming with such a piece of legislation. So what I was thinking was "is it in the